

136

न्यायालय श्रीमान् सदस्य पहोचय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किल कोटि रीवा, जिला रीवामध्ये

राजस्व निगरानी प्रकरण ब्रमांक

R 5201-II/17



मोतीलाल पिता विनायक प्रजापति उप्र वर्ष पेशा खेती,

13-301-

निवासी ग्राम गोदवाली तहसील देवसर जिला सिगरौली मध्ये

----- आवेदक/ निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- जगाहिंद लाल पिता विनायक प्रजापति निवासी गोदवाली तहसील
देवसर जिला सिगरौली मध्ये

2- मध्ये शासन ----- गैरनिगराकारण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्ये

पूराजस्व संहिता सन 1959

विरुद्ध अन्तरिम आदेश 27-4-17

जिसके द्वारा विवादित मुभि नं० 1015/2/

2-020 हे० स्थित ग्राम गोदवाली के संक्षे पै
लेलिक साढ्य हेतु अना०1 को आदेश दियागया
हे जिससे व्यवित होकर

पान्यवर,

प्रकरण का संदिग्ध विवरण :-

प्रकरण का संदिग्ध विवरण इस प्रकार हेकि आ०नं०1०१५/2/

रकवा०2-020 हे० स्थित ग्राम गोदवाली जिला सिगरौली द्वारा

आवेदक के पदा मे जो मैत्रिक भूमि हे, तथा आपसी क्टवारा मे

dr

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ५२०१-॥१७
दो/2017 निगरानी

भाग-अ

जिला सिंगरोली

| स्थान दिनांक | <input checked="" type="checkbox"/> कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|--------------|---|---|
| १५-०९-१७ | <p>यह निगरानी तहसीलदार देवसर वृत्त वरगाँव जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 173 अ-६-अ/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा तहसीलदार देवसर के अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-17 का अवलोकन किया गया। तदनुसार अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम गोंदवाली की भूमि सर्वे नंबर 1015/2 का भूमिस्वामी आवेदक है। वर्ष 2004-05 में हलका पटवारी ने फर्जी प्रकरण क्रमांक 5 अ 19/03-04 में पारित आदेश दिनांक 4-10-04 डालकर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज कर दी गई जबकि भूमि शासकीय है। तहसीलदार व्यारा दायरे को संज्ञान में लेने पर ज्ञात हुआ कि सरल क्रमांक 5 पर प्रकरण आवेदक के नाम दर्ज नहीं है। इन्हीं कारणों से तहसीलदार ने उनके न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक 173 अ-६-अ/2015-16 प्रचलन-योग्य माना है एंव आवेदक की लेखी साक्ष्य के लिये पेशी नियत की है जहाँ आवेदक एंव अनावेदक दोनों को ही पक्ष प्रस्तुत करने का एंव सुनवाई का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश न होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |